# IASbaba-Daily Prelims Test Polity-Hindi [Day 2]

**TOPICS:**

➔ मूल अधिकार (FR) [ Part III ]और मूल कर्तव्य [ Part IV-A ]
➔ राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) [ Part IV ]

1. अनुच्छेद 13 में शब्द 'विधि' शामिल करता है

a) राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी किए गए अध्यादेश
b) संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून
c) कार्यकारिणी द्वारा सूचनाएं
d) उप-विधियां

सही उत्तर चुनिए

1) a, b और c
2) केवल b
3) b और c
4) सभी

ANSWER: 4

अनुछेद 13 के अनुसार , "विधि" शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है -

(अ) स्थायी विधियां , संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियां, जैसे-राजयपालो या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिक विधान ) की प्रकृति में सांविधानिक साधन जैसे - अध्यादेश , आदेश , उपविधि , नियम , विनियम या अधिसूचना।

(द) विधि के गैर - विधायी स्रोत , जैसे - विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा।

iasbaba.com

न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है , अवैध घोषित किया जा सकता है।

Source : Lakshmikanth Chapter 7 'मूल अधिकार'

2. भारतीय संदर्भ में,निम्नलिखित कानून / कार्यक्रम लगातार सरकारों द्वारा तैयार किए गए थे भाग चार के तहत निर्देशों को लागू करने के लिए
   a) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
   b) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987)
   c) त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
   d) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973)

   सही उत्तर चुनिए -

   1) केवल c
   2) a, c और d
   3) a और c
   4) सभी

ANSWER: 4

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्य जीवों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था(=Article 48 A)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) गरीबों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए और समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए, एक देशव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया (=Article 39A)

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (गांव, तहसील और जिला स्तर पर) को चालू किया ताकि गांधी जी का सपना कि हर गांव गणतंत्र हो, साकार हो सके। (=Article 40).

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है। (=Article 50).

iasbaba.com

Source : Lakshmikanth Chapter 8 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व'

3. निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विदेशियों के लिए नहीं हैं?

a) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
b) धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता
c) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
d) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण
e) प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकार

सही उत्तर चुनिए -

1) a और c
2) a, c और e
3) a, b और c
4) b, d और e

ANSWER: 1

मूल अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है :

- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
- सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
- स्वतंत्रता के छह अधिकारों के संरक्षण (अनुच्छेद 19)
- भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
- शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार (अनुच्छेद 30)

Source : Lakshmikanth Chapter 7 'मूल अधिकार'

4. 'संपत्ति का अधिकार' भारत के संविधान में अपनी स्थापना के बाद से प्रमुख विवाद में था । वर्तमान स्थिति के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार कीजिये :

iasbaba.com

a) यह एक संवैधानिक अधिकार है
b) सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के उल्लंघन के लिए, क़ानूनी क्षेत्राधिकार जारी कर सकते हैं।
c) संपत्ति के अधिकार 42th संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था

सही उत्तर चुनिए -

1) केवल c
2) a केवल
3) a और b
4) a और c

ANSWER: 2

44वे संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरसित किया गया। "संपत्ति का अधिकार" शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 A को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गयी कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक क़ानूनी या संवेधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है।

Source : Lakshmikanth Chapter 7 'Fundamental Rights'

5. भारतीय संदर्भ में, कानून के समक्ष समानता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिये

a) संसद का सदस्य संसद में उनके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान या किसी भी संबंध में कहे हुए के प्रति अदालत को जवाबदेह है
b) राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक उन्मुक्ति का लाभ लेते हैं

iasbaba.com

c) विदेशी राजदूतों और राजनयिकों न केवल आपराधिक उन्मुक्ति बल्कि सिविल उन्मुक्ति का लाभ लेते है

सही उत्तर चुनिए -

1) a और c
2) a और b
3) b और c
4) a, b और c

**ANSWER: 3**

समता के अपवाद

- राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य पर किये गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायलय ही दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
- संसद में या किसी भी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गयी किसी बात या दिए गए किसी मत के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायलय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- विदेशी सम्प्रभु (शासक), राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति , दीवानी एवं फौजदारी मुकदमो से मुक्त होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।

.

Source : Lakshmikanth Chapter 7 'मूल अधिकार'

6. अनुच्छेद 19, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को छह अधिकार (स्वतंत्रता का अधिकार) की गारंटी देता है । स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये :

a) आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है

iasbaba.com

b) वेश्याओं के गमनागमन की स्वतंत्रता को सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है

सही उत्तर चुनिए :

1) केवल a
2) केवल b
3) दोनों a और b
4) कोई नहीं

ANSWER: 3

स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हैं, आम जनता के हितों के लिए और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज और अनुसूचित जनजातियों के शिष्टाचार की रक्षा के लिए और उनके पारंपरिक व्यवसाय की रक्षा और संपत्तियों की शोषण से रक्षा के लिए प्रतिबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्याओं के गमनागमन की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है । बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स से प्रभावित लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध मान्य किया।

Source : Lakshmikanth Chapter 7 'मूल अधिकार

,

7. भारतीय संदर्भ में, 'विधि की विधिवत प्रक्रिया' की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन से मामले/अधिनियम के तहत पेश किया गया ?

1) मिनर्वा मिल्स मामला
2) केशवानंद भारती मामला
3) मेनका गांधी मामला
4) 44 वें संशोधन अधिनियम

iasbaba.com

ANSWER: 3

मेनका मामले (1978) में उच्चतम न्यायलय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायलय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक जा सकता है
बशर्ते ये विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो । दूसरे शब्दों में, यह अमेरिकी अभिव्यक्ति 'विधि की विधिवत प्रक्रिया' है।

Source : Lakshmikanth Chapter 7' मूल अधिकार"'

8. निम्नलिखित पर विचार कीजिये :

**Assertion (A):** निर्देशक तत्व प्रकृति में गैर-न्यायोचित हैं

**Reason (R) :** कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 (ख) और अनुच्छेद 39 (ग) में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रभाव देता है और कानून की प्रक्रिया में अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तो कानून असंवैधानिक नहीं माना जाता है

सही उत्तर चुनिए :

1) दोनों A और R सही है और R A का सही स्पष्टीकरण है
2) दोनों A और R सही है और R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
3) A सही है और R गलत है
4) A गलत है और R सही है

**ANSWER: 2**

वाक्यों पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें तो Assertion और Reasoning दोनों सही हैं। लेकिन Assertion में कहा गया है कि R सही reasoning नहीं है।

निदेशक तत्व प्रकृति में गैर-न्यायोचित हैं यानि कि वे अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं । इसलिए, सरकार (केन्द्र, राज्य और स्थानीय) को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

iasbaba.com

कथन (R) एक सही वाक्य  है। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट (1980)  घोषित किया DPSP मूल अधिकार के अधीनस्थ है मगर मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को  DPSP के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के तहत अधिनस्त स्वीकार किया गया था।

Source : Lakshmikanth Chapter 8 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व '

9. भारतीय संविधान के अनुसार, निम्न में से कौनसा मौलिक कर्तव्य नहीं है ?

    1) जनता चुनाव में मतदान करने के लिए
    2) वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए
    3) 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए।
    4) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए

ANSWER: 1

चुनावों में मतदान करना  और करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं हैं ।

Source : Lakshmikanth Chapter 9 'मूल कर्तव्य '

10. भारत के संविधान में निहित के रूप में राज्य के नीति निदेशक  तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें।

    a) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए।
    b) समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए।
    c) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए
    d) राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए
    e) देश भर में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए

iasbaba.com

उपर्युक्त में से कौन से स्वतंत्र-बौद्धिक सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिलक्षित होते हैं?

1) a, c, d और e
2) a, d और e
3) c, d और e
4) सभी

**ANSWER : 3**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन गरीब DPSP के गांधीवादी सिद्धांतों के तहत है जबकि बराबर न्याय और नि: शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना DPSP की समाजवादी सिद्धांतों के तहत है ।

Source : Lakshmikanth Chapter 8 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व '

iasbaba.com